भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2919

दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को उत्तर देने के लिए

लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूआईडीएआई के लिए संस्वीकृत निधियां

2919. डा. के. पी. रामालिंगमः

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 2015 के अंत तक 10 करोड़ नागरिकों का नाम दर्ज करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को 1200 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि 2015 के अंत तक उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ लोगों को यूआईडीएआई कार्ड प्राप्त करना है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - योजना मंत्रालय,

तथा रक्षा राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 10.09.2014 को आयोजित अपनी बैठक में यूआईडीएआई को नामांकन हेतु आबंटित चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में 31.62 करोड़ जनसंख्या के लिए आधार नामांकन करने हेतु 1265 करोड़ रु. के अतिरिक्त परिव्यय को अनुमोदित किया है। 14 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार, इसमें से इन चार राज्यों के कुल 10.31 करोड़ निवासियों को आधार जारी कर दिए गए हैं और देश में सृजित आधार की कुल संख्या 72.24 करोड़ है।